# फसल अनुसंधान को बजट में मिले प्रोत्साहन : डॉ. शिवेन्द्र बजाज

नई दिल्ली (ए)। एग्री बायोटेक उद्योग ने कृषि अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देने, किसानों की आय सुधारने और भारतीय कृषकों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए बजट 2016 में उपाय किये जाने का आग्रह करते हुए कहा है कि फसल अनुसंधान को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इस उद्योग के प्रमुख संगठन 'एसोसिएशन ऑफ बायोटेक लेड एन्टरप्राइजेज : एग्रीकल्चर फोकस्ड ग्रुप' के कार्यकारी निदेशक डॉ शिवेन्द्र बजाज ने कहा कि वर्ष 2015-16 के आधार पर देश में एग्री बायोटेक्नोलॉजी उद्योग एक मोड़ पर खड़ा है।

नई प्रौद्यौगिकियों के द्वारा भारतीय कृषि और किसानों की आजीविका में सुधार की ऐसे लोग अनदेखी कर रहे हैं, जिन्हें भारतीय शोधकर्ताओं की क्षमता पर या वैज्ञानिक प्रगति पर भरोसा नहीं है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ, जिनकी एग्री-बायोटेक क्षेत्र में महत्वाकांक्षी योजनाएँ हैं, प्रतिभा और बुनियादी संरचनाओं पर पर्याप्त निवेश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा और फायदों के मूल्यांकन के बगैर देश में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों द्वारा फसल प्रौद्यौगिकी में किया गया 12 हजार करोड़ रुपये का निवेश जोखिम में पड़ सकता है। सुरक्षा को लेकर इसी तरह के भय के कारण वर्ष 2005 के बाद से कृषि क्षेत्र में कोई नया जैव प्रौद्यौगिकी इनोवेशन नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि बीटी ब्रिंजल पर वर्ष 2010 में रोक लगा दी गई, जबकि बंगलादेश इसी प्रोद्यौगिकी के साथ आगे बढ़ गया। हालाँकि, एग्री बायोटेक्नोलॉजी एकमात्र प्रोद्यौगिकी नहीं है, लेकिन जब सरकार कृषि क्षेत्र के नवीनीकरण को लेकर गम्भीर हो तो यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एग्री-बायोटेक्नोलॉजी के साथ कृषि में पारम्परिक कृषि और जैविक खेती का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।

डॉ. बजाज ने कहा कि वर्ष 2020 तक देश में खाद्य पदार्थों की माँग दुगुणी हो जायेगी। खान-पान की आदतें बदल रही हैं। अनाज का उपभोग कम हो रहा है, जबकि अण्डे, मछली, दूध और माँस का उपभोग बढ़ रहा है। माँस के हर किलोग्राम के लिए पाँच किलोग्राम चारे की आवश्यकता होती है। खाद्य तेलों की माँग दोगुनी होकर 3.4 करोड़ टन तक पहुँच जायेगी। अगर कारोबार सामान्य बना रहता है तो इनका आयात वर्तमान 90 लाख टन के आँकड़े से बढ़कर वर्ष 2030 तक 1.9 करोड़ टन पर पहुँच जायेगा।

**'नई प्रोद्यौगिकियों के द्वारा कृषि व किसानों की आजीविका में सुधार की अनदेखी की जा रही'**

इसी तरह दालों की माँग और आयात में भी बढ़ोतरी होगी। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एवं कृषि संस्था एफएओ की रिपोर्ट के अनुसार, भारत चावल, गेहूँ और दालों के विश्वस्तरीय औसत उत्पादन की दृष्टि से अभी पीछे है। पानी का भण्डारण, उच्च उत्पादकता के बीजों की कमी तथा अनुसंधान एवं विकास की कमी भारत में प्रति हेक्टेयर कम उत्पादन के मुख्य कारण हैं। उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादकता में सुधार लाना होगा और भारतीय अनुसंधानकर्ताओं को फसल अनुसंधान के नये क्षेत्रों पर काम करना होगा - जैसे स्टेम सेल रिसर्च, नैनोटेक्नोलॉजी आदि। इसे सम्भव बनाने के लिए एग्री-बायोटेक को नीतिगत वातावरण उपलब्ध कराना होगा ताकि इसमें अपेक्षित निवेश को बढ़ावा दिया जा सके। बीजों से सम्बन्धित नियम, जैव प्रोद्यौगिकी विनियम तथा जैव विविधता का संरक्षण इस दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। वर्ष 2015-16 की आर्थिक समीक्षा में भी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृषि क्षेत्र में व्यापक बदलाव, सिंचाई की व्यवस्था को बेहतर बनाने, उर्वरकों पर सब्सिडी को युक्तिसंगत कर उन्हें सीधे किसानों के खाते में हस्तांतरित करने, जीएम फसलों का सही मूल्यांकन करने तथा बीजों की उपलब्धता बढ़ाने की आवश्यकता बताई गई है। उत्पादकता बढ़ाने के लिए समीक्षा में उर्वरकों और उन्नत बीजों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने और किसानों के लिए उसकी उपलब्धता आसान बनाने के लिए इन पर दी जाने वाली सब्सिडी सीधे उनके खातों में पहुँचाने की व्यवस्था पर जोर दिया गया है। उन्नत बीजों के लिए बीज प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। बीजों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इस दिशा में अनुसंधान को प्रोत्साहित किये जाने पर बल देते हुये आनुवांशिक रूप से संवर्द्धित फसलों (जीएम) के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि बीजों की संकर और अधिक उपज देने वाली किस्मों का उपयोग देश में कृषि उत्पादकता बढ़ाने का मुख्य जरिया बनेगी।